Offer by Employees Union to restart M/s Mafatlal Engineering Industries Ltd.

3524. SHRI SATISH PRADHAN: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether it is a fact that M/s Mafatlal Engineering Industries Ltd. (earlier known as National Machinery Manufactures Ltd.), Thane have suspended production;

(b) whether it is also a fact that Mafatlal Engineering Industries Employees Union have offered to restart the operations;

(c) if so, what action has been taken to consider this offer and whether any efforts have been made to restart the Industry?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI P. A. SANGMA): (a) to (c) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

नये राशन कार्डों के लिये आवेदन

3525. **श्री अजीत जोगी :**
चौधरी हरि सिंह :

क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले छः महीने के दौरान नये राशन कार्ड जारी कराने के लिये दिल्ली प्रशासन के खाद्य और पूर्ति विभाग को जोन-वार कितने-कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुये हैं ;

(ख) अब तक कितने राशन कार्ड जारी किये गये हैं ; और

(ग) शेष आवेदकों को कब तक राशन कार्ड जारी कर दिये जाने की संभावना है ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) गत 6 महीनों के दौरान नये राशन कार्ड जारी करने के लिये प्राप्त आवेदनों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की सरकार द्वारा जारी किये गये राशन कार्डों का ब्यौरा निम्नवत हैं:—

क्षेत्र का नाम	प्राप्त आवेदनों की संख्या	जारी किये गये राशन कार्डों की संख्या	रद्द किये गये आवेदन	लंबित
दक्षिणी	11657	10742	587	328
उत्तरी	3132	2659	473	—
केन्द्रीय	4564	4030	534	—
पश्चिमी	15610	14178	1345	87
उत्तर-पूर्वी	10455	9705	279	471
पूर्वी	9890	8625	41	1224
उत्तर-पश्चिमी	16183	15487	617	79
दक्षिण-पश्चिमी और नई दिल्ली	11893	11165	728	—
योग :	83384	76591	4604	2189

(ग) शेष आवेदनों को शीघ्र निपटाने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं।

गरीबों में खाद्यान्न का वितरण

3526. **श्री अजीत जोगी** : क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि उत्पादों के संबंध में अमरीका और युरोपीय समुदाय के बीच हुये समझौते के कारण देश में गरीब लोगों के बीच खाद्यान्नों के वितरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये जाने का विचार है?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) सरकार देश की खाद्य सुरक्षा जरूरतों विशेषकर गरीब लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त उपाय करती है और इसके लिए वह कृषि उत्पादन में वृद्धि करने, लाभकारी मूल्यों के जरिए अभिप्राप्ति में वृद्धि करने, आवश्यकता होने पर आयात करने तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को राजसहायता देने के प्रयास करती है।

Profit and loss in Super Bazar

3527. SHRI SARADA MOHANTY: Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) the details of balance-sheet of profit and loss of Super Bazar, issued by the Audit and Chartered Report for last five years;

(b) the number of the dividends paid by the Super Bazar Authority to the share-holders till 31st July, 1993;

(c) whether it is a fact that action has been taken to recover the amount which has already been paid as dividend to the share holders;

(d) what are the details of total number of public funds blocked with Super-Bazar and fraud of public funds made by Super Bazar;

(e) whether Government have ordered any CBI investigation against Super Bazar so far; and

(f) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI KAMALUDDIN AHMED): (a) The Annual Report and audited accounts of Super Bazar containing details of balance sheet, profit and loss are being laid every year on the Table of the House, and last such one was for the year 1991-92.

(b) Super Bazar has been paying dividend to shareholders w.e.f. the year 1982-84 to 1991-92.

(c) The amount of dividend paid to the shareholders is not recoverable.

(d) Under the Central Sector Scheme for the development of the Co-operative Stores Ltd., Super Bazar, New Delhi, the funds are released to Super Bazar as share capital, loan and subsidy for augmentation of its business, opening of Branches as well as for creating other infrastructure. Super Bazar is repaying loan with interest and also redeeming share capital and dividend regularly to the Government of India. Hence, there is no blockade of funds with Super Bazar and nothing has come in the notice regarding any fraud of public funds by Super Bazar.